RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 07 AUGUST TO 13 AUGUST 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 46 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

IOC, BPCL और HPCL का मुनाफा 90% तक घटा,
Page 2

RBI ने 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखी जीडीपी ग्रोथ रेट, जानें महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं
Page 3

बजट ने मिडिल क्लास के टैक्स का बोझ घटाया LTCG में बदलाव लोगों की उम्मीदः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Page 5

editoria!

भारत के लिए चुनौतियां

बीते कई दशकों में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध उत्तरोत्तर बेहतर हुए हैं. द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हमारे देश में कभी कोई राजनीतिक मतभेद भी नहीं रहा है. भारत में सरकार चाहे किसी दल या गठबंधन की हो, बांग्लादेश हमारा निकटतम पड़ोसी बना रहा है. इस पृष्ठभूमि में वहां जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक घटनाएं अनेक कारणों से भारत के लिए चिंताजनक हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि भारतीय उच्चायोग के माध्यम से सरकार वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है. साथ ही, सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के भी संपर्क में है. बांग्लादेश में लगभग 19 हजार भारतीय हैं, जिनमें नौ हजार के करीब छात्र हैं. जुलाई में बहुत से छात्र देश वापस आ गये हैं. भारत सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लेकर भी चिंतित है. विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के उन समूहों और संस्थाओं की सराहना की है, जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में जुटे हैं. परस्पर संबंधों के बहुत अच्छे होने के कारण वहां भारत के संपर्क सूत्रों एवं केंद्रों की कमी नहीं है. राजधानी ढाका में उच्चायोग के साथ-साथ चार महत्वपूर्ण शहरों में हमारे सहायक उच्चायोग भी हैं. प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं है, बल्कि वह उग्र ही होता जा रहा है. पुलिस हड़ताल पर है और ऐसा लगता है कि सेना हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में हिचक रही है. ऐसे में वहां से भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थियों के आने की आशंकाएं भी हैं. बांग्लादेश और म्यांमार से शरणार्थी आते रहे हैं. विदेश मंत्री जयशंकर ने आश्वस्त किया है कि सीमा सुरक्षा बल को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्वोत्तर को भरोसा दिलाया है कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. भारत और बांग्लादेश की सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम सीमावर्ती राज्य हैं. वर्ष 2021 में जब म्यांमार में हालात बिगड़े थे, तब मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली थी. आकलनों के अनुसार, मिजोरम में अभी भी 35 हजार से अधिक शरणार्थी हैं. मणिपुर में हालिया अशांति में भी यह मसला एक कारक रहा है. अनेक राज्यों, विशेषकर असम, में बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक रूप से दशकों से संवेदनशील रहा है. यह मसला हिंसा की वजह भी बना है. वे सब अनुभव बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब नयी आशंकाओं का आधार बन रहे हैं. सर्वदलीय बैठक और संसद में विदेश मंत्री का बयान यह इंगित करते हैं कि हमेशा की तरह हमारे देश में संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक एकता बनी हुई है तथा सरकार अपने स्तर पर यथासंभव प्रयास कर रही है.

अमेरिका-जर्मनी पर मंदी का संकट, चीन खस्ताहाल और भारत बनने जा रहा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका पर मंदी के काले बादल मंडरा रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी से ये चिंताएं व्यापक हो गई हैं। वहीं, यूरोप की सबसे बड़ी और अमेरिका, चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जर्मनी भी मंदी के कगार पर है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिली है। उधर चीन की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। चीनी अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। जापान की इकोनॉमी पर भी इस समय कई संकट हैं। इन सब के बीच भारत सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ करता जा रहा है।

जल्द भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी

इस समय भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत से ऊपर जापान, जर्मनी, चीन और अमेरिका हैं। जापान और जर्मनी के खस्ताहाल को देखते हुए भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब उपराष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार

को कहा कि भारत की प्रगति को रोका नहीं जा सकता और देश दो साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा, " हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम दो साल या उससे भी कम समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।"

उपराष्ट्रपति ने की आर्थिक राष्ट्रवाद की वकालत

उपराष्ट्रपति ने 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि यदि हम जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सोचें, तो हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए इसका इष्टतम उपयोग किया जाएगा, जो समय की मांग है, देश की तथा पृथ्वी की जरूरत है। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' आह्वान के मूल में आर्थिक स्वतंत्रता है। हथकरघा उत्पाद इसके प्रमुख तत्वों में से एक हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद की जोरदार वकालत करते हुए धनखड़ ने कहा कि यह देश की "आधारभूत आर्थिक वृद्धि" के लिए मौलिक है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार सृजन तथा उद्यमिता को बढ़ावा सहित तीन प्रमुख प्रभाव होंगे।

आर्थिक राष्ट्रवाद का त्याग नहीं कर सकते

उपराष्ट्रपति ने कहा, "मैं चाहता हूं कि हर कोई राष्ट्रीय हित का सम्मान करे। क्या हम केवल राजकोषीय लाभ के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद का त्याग कर सकते हैं?" धनखड़ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और आज कोई भी यह कह सकता कि हमारा संभावनाओं से भरा राष्ट्र हैं, क्योंकि हम प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे साड़ी, कुर्ते, शॉल आदि हथकरघा उत्पाद खरीदने की आदत बनाने का संकल्प लें, ताकि यह एक 'फैशन स्टेटमेंट', एक ब्रांड बन जाए और इसकी बिक्री बढ़े।

भारत ने 2023-24 में किया रिकॉर्ड 36.43 बीसीएम गैस का उत्पादन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) गैस का उत्पादन किया। देश की इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनर्जी के क्षेत्र में भारत की 'आत्मनिर्भरता' की सराहना की। पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, 'इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई! एनर्जी के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। गैस उत्पादन का ये रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।'

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक एक्स पोस्ट में बताया था कि देश ने गैस उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। 2020-21 में गैस का उत्पादन 28.7 बीसीएम था। 2023-24 में इसे बढ़ाकर 36.43 बीसीएम कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि साल 2026 में भारत द्वारा किया जाने वाला गैस का उत्पादन 45.3 बीसीएम होगा। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, 'आंकड़े प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतवर्ष एक नई ऊर्जा, नई उमंग व नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में देश ने गैस उत्पादन के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए आत्मनिर्भरता की गति को और तेजी दी है।'

इससे पहले 29 जुलाई को हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां फ्यूल की कीमतें वास्तव में कम हुई हैं। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पुरी ने कहा था, 'आज भारत में ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं और ये एकमात्र ऐसा देश है, जहां पिछले 2.5-3 सालों में कीमतों में वास्तव में कमी आई है।

बांग्लादेश संकटः व्यापार पर मंडराया संकट का बादल

राम एस. पाल

इंदौर। बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल का भारत के व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है। देश में फैली अशांति के कारण भारत से बांग्लादेश जाने वाले कई तरह के सामानों का निर्यात बाधित हो गया है। कपड़े, मशीनरी, खाद्य पदार्थों के साथ-साथ जूट और मछली जैसे उत्पादों का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश में डॉलर की भारी कमी के कारण भारत से आयात करने की क्षमता भी कम हो गई है। इसके अलावा, सीमा पर सुरक्षा बढ़ने और माल की आवाजाही में बाधाएं आने से निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासकर, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का निर्यात सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'बांग्लादेश में संकट के कारण हमें कुछ व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी और व्यापार को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।' हालांकि, पश्चिम बंगाल के निर्यातक संजय बुधिया का मानना है कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों के कारण इस संकट का भारत के व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से कई क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत के व्यापार पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

IOC, BPCL और HPCL का मुनाफा 90% तक घटा, जानें क्यों आई गिरावट और क्या होगा स्टॉक पर असर

नई दिल्ली। एजेंसी

रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (द्दध्ण), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (ँझ्ण्थ) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (प्झ्ण्थ) के अप्रैल-जून तिमाही के मुनाफे में 90 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। मुनाफे में गिरावट की प्रमुख वजह रसोई गैस (थ्झ्ड) की लागत से कम दाम पर बिक्री है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी आईओसी का अप्रैल-जून तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 81 प्रतिशत घटा है। यह चालू वित्त वित्त की पहली तिमाही में 2,643.18 करोड़ रुपये रहा है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 13,750.44 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। तिमाही आधार पर भी कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई है। इससे पिछली जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11,570.82 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही के दौरान एचपीसीएल का मुनाफा 90 प्रतिशत घटकर 633.94 करोड़ रुपये रह गया। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आने का असर इन कंपनियों के स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक में गिरावट आ सकती है।

इस कारण मुनाफा में आई गिरावट

बीपीसीएल का शुद्ध लाभ अप्रैल-जून में घटकर 2,841.55 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 10,644.30 करोड़ रुपये और जनवरी-मार्च तिमाही में 4,789.57 करोड़ रुपये था। तीनों ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने पिछले साल लागत में गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखकर अत्यधिक मुनाफा कमाया था। इन कंपनियों का तर्क था कि इससे पिछले साल लागत बढ़ने के बावजूद उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए थे और नुकसान उठाया था। हालांकि, कीमतों को 'फ्रीज' करने का लाभ आम चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में दो-दो रुपये प्रति लीटर की कटौती से जाता रहा। इसके अलावा, तीनों पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी की लागत से कम बिक्री पर सब्सिडी नहीं मिली है।

किस कंपनी को कितना नुकसान हुआ

इन कंपनियों द्वारा शेयर बाजारों को भेजी सूचना के अनुसार, आईओसी को अप्रैल-जून में एलपीजी की लागत से कम दाम पर बिक्री से 5,156.23 करोड़ रुपये, बीपीसीएल को 2,015.10 करोड़ रुपये और एचपीसीएल को 2,443.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, जब एलपीजी सिलेंडर की बाजार निर्धारित कीमत (एमडीपी) ग्राहक के लिए इसकी प्रभावी लागत (ईसीसी) से कम होती है, तो पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भविष्य के समायोजन के लिए इस अंतर को एक अलग बफर खाते में रखना होता है। तीन पेट्रोलियम कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 81,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज कमाया था।

सरकारी कंपनी ओएनजीसी को झटका, 15% घट गया मुनाफा, जानिए वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकारी स्वामित्व वाली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 15 प्रतिशत घट गया। कंपनी ने बताया कि अधिक अन्वेषण लागत को बट्टे खाते में डालने की वजह से उसके मुनाफे में गिरावट आई है। ओएनजीसी ने शेयर बाजार को बताया कि चालू वित्त वर्ष (2024-25) की अप्रैल-जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 8,938.10 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 10,526.78 करोड़ रुपये था। मुनाफा इससे पिछली तिमाही जनवरी-मार्च के 9,869.37 करोड़ रुपये की तुलना में भी कम रहा।

1,669.73 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डाले

ओएनजीसी ने तेल एवं गैस खोज के लिए सर्वेक्षण और कुओं की खुदाई में खर्च हुए 1,669.73 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डाल दिया, क्योंकि ये प्रयास असफल रहे। इसकी तुलना में अप्रैल-जून 2023 में यह आंकड़ा 1,015.81 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय एक साल पहले के 33,814.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,266.38 करोड़ रुपये हो गई। बट्टे खाते में अधिक राशि डालने से कंपनी को तेल की कीमतों में वृद्धि से होने वाले लाभ पर असर पड़ा। जून तिमाही में ओएनजीसी को कच्चे तेल के उत्पादन पर 80.64 डॉलर प्रति बैरल मिले, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह राशि 70.64 डॉलर प्रति बैरल थी।

पांच तेल और गैस ठिकानों की खोज की

कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसका तेल उत्पादन 46.29 लाख टन पर लगभग स्थिर रहा। हालांकि, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 3.6 प्रतिशत घटकर 4.86 अरब घन मीटर रह गया। ओएनजीसी ने कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल पांच तेल और गैस ठिकानों की खोज की हैं, हालांकि कंपनी ने न तो भंडार अनुमान दिया और न ही संभावित उत्पादन के बारे में बताया।

BSE का पहली तिमाही में 3 गुना बढ़ गया मुनाफा NSE का प्रॉफिट 39% बढ़ा, सरकार को पहुंचे 14,000 करोड़

मुंबई। एजेंसी

देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में तीन गुना से अधिक होकर 265 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 75 करोड़ रुपये रहा था। बीएसई ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी आमदनी जून तिमाही में 674 करोड़ रुपये रही है, जो किसी तिमाही में उसका अबतक का सर्वाधिक है। पिछले साल समान तिमाही में उसकी आमदनी 271 करोड़ रुपये थी। बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदररमन राममूर्ति ने कहा, "पहली तिमाही में हमारा प्रदर्शन मजबूत रहा है। प्रत्येक कारोबार ने आय और लाभ में योगदान दिया है।"

एनएसई का मुनाफा 39% बढ़ा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का जून, 2024 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,567 करोड़ रुपये हो गया। एनएसई की चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में एकीकृत परिचालन आय 51 प्रतिशत बढ़कर 4,510 करोड़ रुपये हो गई। एकल आधार पर एनएसई ने समीक्षाधीन तिमाही में 1,960 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,598 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में एनएसई ने 4,051 करोड़ रुपये की कुल परिचालन आय दर्ज की, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 2,833 करोड़ रुपये से साल-दर-साल आधार पर 43 प्रतिशत की वृद्धि है। समीक्षाधीन तिमाही में एनएसई का एकल आधार पर कुल खर्च 1,762 करोड़ रुपये रहा।

सरकारी खजाने में गये 14,003 करोड़ रुपये

एनएसई ने कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सरकारी खजाने में 14,003 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसमें से एसटीटी/सीटीटी (कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) में 12,054 करोड़ रुपये, स्टाम्प शुल्क (1,018 करोड़ रुपये), जीएसटी (362 करोड़ रुपये), सेबी शुल्क (333 करोड़ रुपये) और आयकर (236 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

अब सिर्फ कुछ ही घंटों में 'क्लियर' हो जाएगा आपका चेक, आरबीआई गवर्नर ने दिया ये बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। एजेंसी

आरबीआई एक जल्द चेक क्लियरेंस के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है। इस नए सिस्टम के तहत आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा।चेक क्लियरेंस के लिए अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, अब कुछ ही घंटों में आपका चेक क्लियर हो जाएगा और आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरिंग में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कदम उठाने का फैसला किया है।

अभी चेक क्लियर होने में लगता है 2 दिन का समय

वर्तमान में चेक जमा करने से लेकर चेक क्लियर होकर पैसे आने में कम से कम दो दिन का समय लग जाता है। लेकिन नए सिस्टम में चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में ये क्लियर हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा की घोषणा करते हुए इसका ऐलान किया।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम में बदलाव का प्रस्ताव

शक्तिकांत दास ने कहा, "चेक क्लियरिंग को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के मौजूदा सिस्टम में बदलाव का प्रस्ताव है।" उन्होंने कहा कि नए सिस्टम में मौजूदा सीटीएस व्यवस्था के तहत 'बैच' में प्रोसेसिंग की जगह कारोबारी समय (Working Hours) में निरंतर आधार पर क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी।

नए सिस्टम में स्कैन किया जाएगा चेक

आरबीआई के मुताबिक, "नई व्यवस्था में चेक को 'स्कैन' किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ घंटों में क्लियर किया जाएगा। इससे चेक का क्लियरेंस कुछ घंटे में हो जाएगा जबकि अभी दो दिन तक का समय (ऊ्1) लगता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि इस मामले में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएगी।

टैक्स पेमेंट के लिए यूपीआई लिमिट में बढ़ोतरी

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके अलावा आज और भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अब यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने आज रेपो रेट को लगातार 9वीं बार 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का ऐलान किया।

RBI ने 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखी जीडीपी ग्रोथ रेट, जानें महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का गुरुवार को ऐलान किया। आरबीआई ने इसके साथ ही देश की इकोनॉमी पर भी कई अहम जानकारी दी। आरबीआई ने सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के बीच चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2 प्रतिशत पर कायम रखा है। रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई दर के अनुमान को भी 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

शक्तिकांत दास ने कहा कि दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू-आर्थिक विखंडन के कारण नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मानसून में तेजी से महंगाई में कुछ राहत की उम्मीद

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गवर्नर ने महंगाई पर कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में तेजी से खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बुवाई में अच्छी प्रगति हुई है और अनाज का भंडार (बफर स्टॉक) अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा बना हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य कीमतों में मार्च, 2024 से बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद जुलाई में कमी के संकेत मिले हैं।

चालू वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत महंगाई दर का अनुमान

गवर्नर ने कहा कि सामान्य मानसून के पूर्वानुमान और पहली तिमाही में 4.9 प्रतिशत महंगाई को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में 4.3 प्रतिशत रहेगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति अपेक्षा से ज्यादा रहने के कारण जून, 2024 में मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई थी।

ऐतिहासिक निचले स्तर पर आई कुल मुद्रास्फीति

उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन की महंगाई लगातार 10वें महीने कम हुई और मई-जून में कुल मुद्रास्फीति ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों का सिलसिला जुलाई में भी जारी रहने की संभावना है। हालांकि, अनुकूल आधार प्रभाव से महीने के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि दूध की कीमतों और मोबाइल टैरिफ में संशोधन के प्रभाव पर नजर रखने की जरूरत है।

RBI ने बढ़ाई UPI Transaction की लिमिट

जानें किन लोगों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर बड़ा ऐलान किया। आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सुविधाओं की वजह से आज ऑनलाइन पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। फिलहाल, यूपीआई के लिए टैक्स भुगतान की लिमिट एक लाख रुपये है।

टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ाई गई यूपीआई लिमिट

शक्तिकांत दास ने कहा कि अलग-अलग उपयोग-मामलों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर कैपिटल मार्केट, आईपीओ, इंश्योरेंस, मेडिकल और एजुकेशनल सर्विसेज आदि जैसी कुछ कैटेगरी के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। शक्तिकांत दास ने कहा, ''चूंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के हैं। इसलिए यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला लिया गया है। इस मामले में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।''

42.4 करोड़ हुआ यूपीआई यूज़र बेस

आरबीआई के मुताबिक, यूपीआई का यूज़र बेस 42.4 करोड़ हो गया है। हालांकि, यूज़र बेस में और विस्तार की संभावना है। यूपीआई में डेलिगेटेड पेमेंट्स शुरू करने का भी प्रस्ताव है। शक्तिकांत दास ने कहा कि 'डेलिगेटेड पेमेंट्स' से एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते पर किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी।

लगातार 9वीं बार स्थिर रखा गया रेपो रेट

बताते चलें कि आरबीआई ने आज लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 6 अगस्त को शुरू हुई आरबीआई एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए शक्तिकांत दास ने आज बड़ा ऐलान करते हुए रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का ऐलान किया।

चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी बने भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नए चेयरमैन अब सी एस सेट्टी (चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी) होंगे। सरकार ने मंगलवार को सेट्टी को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया। वह 28 अगस्त को बैंक के मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त करने के वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

खारा 28 अगस्त को रिटायर होंगे

खबर के मुताबिक, खारा 28 अगस्त को रिटायर होंगे, जब उनकी आयु 63 वर्ष हो जाएगी, जो एसबीआई चेयरमैन पद के लिए अधिकतम आयु सीमा है। इसके अलावा, सरकार ने राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई में प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई में एक चेयरमैन है, जिसके सहायक चार एमडी हैं। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि सिंह, जो वर्तमान में

डीएमडी हैं, 30 जून, 2027 को एमडी के रूप में काम करेंगे, जो रिटायरमेंट की आयु है।

1988 में एसबीआई के साथ करियर की शुरुआत

सेट्टी, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न टास्क फोर्स और समितियों का भी नेतृत्व किया, ने पहले बैंक के खुदरा और डिजिटल बैंकिंग पोर्टफोलियो की देखभाल की थी। कृषि में विज्ञान स्नातक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट, उन्होंने 1988 में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एसबीआई के साथ अपना करियर शुरू किया। उन्हें कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल, डिजिटल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और विकसित बाजारों में बैंकिंग का समृद्ध अनुभव है।

देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने का रास्ता साफ

असम में फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ, जानें कब से होगा प्रोडक्शन

असम। एजेंसी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और टाटा संस लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शनिवार को मोरीगांव जिले के जागीरोड में 27,000 करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर (चिप) निर्माण और परीक्षण संयंत्र का भूमि पूजन किया। जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र, भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र है। सरमा और चंद्रशेखरन, दोनों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर संयंत्र के 3-डी मॉडल का अनावरण किया गया। सरमा ने कहा कि यह असम के लोगों के लिए 'स्वर्णिम दिन' है और उन्होंने इस संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और टाटा संस लिमिटेड को धन्यवाद दिया।

फैक्ट्री के निर्माण में कोई समस्या नहीं आएगी

मुख्यमंत्री ने टाटा संस लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आश्वासन दिया कि कंपनी को इस संयंत्र की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं होगी और असम के लोग इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल के कारण यह संयंत्र असम में आ सका। सरमा ने कहा, ''उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अगर टाटा एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो केंद्र असम में संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए दो कदम आगे बढ़ेगा।'' राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में कमी आने के बाद भी बहुत कम निजी कंपनियां राज्य में निवेश करने को तैयार थीं, लेकिन सरमा ने कहा, ''मैंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी, गुवाहाटी) का सह-प्रायोजक बनने के लिए चंद्रशेखरन से संपर्क किया था, जो उस समय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक थे, और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी थी।'' सरमा ने कहा कि टाटा असम के लिए नई नहीं हैं और वे चाय उद्योग, कैंसर देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, ऑटोमोटिव और अब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई क्षेत्रों में यहां काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''टाटा देश के किसी भी राज्य में यह उद्योग स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने असम को चुना और हम इसके लिए आभारी हैं।''

1,000 लड़कियों की भर्ती की जा चुकी

उन्होंने कहा कि टाटा ने आश्वासन दिया था कि स्थानीय युवाओं को नियुक्त किया जाएगा और पहले ही 1,000 लड़कियों की भर्ती की जा चुकी है। चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा समूह स्थानीय युवाओं को काम पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए 1,000 लड़कियों की भर्ती की जा चुकी है और ''हमें यकीन है कि वे राज्य और देश का भविष्य बनाएंगी और उसे आकार देंगी।'' उन्होंने यह भी कहा कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने परियोजना और असम के लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि संयंत्र चालू होने के बाद यह असम के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा और वृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल 13 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस संयंत्र की आधारशिला रखी थी।

27,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा

जागीरोड में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की अत्याधुनिक परियोजना में 27,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। संयंत्र का पहला चरण 2025 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि प्रस्तावित संयंत्र एआई, औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख बाजार क्षेत्रों में बढ़ती वैश्विक मांगों को पूरा करेगा। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में औद्योगीकरण को बढ़ावा देगी।

4 महीने में भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया 2.6 लाख टन प्याज

इस बार दोगुनी से ज्यादा मिली कीमतें

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत ने चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात किया है। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''सरकार ने चार मई, 2024 से प्याज पर प्रतिबंध हटा लिया है और 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ निर्यात की अनुमति दी है।'' उन्होंने कहा, ''31 जुलाई, 2024 तक चालू वित्त वर्ष में कुल 2.60 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था।''

पिछले साल 16.07 लाख टन प्याज का किया था निर्यात

भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 16.07 लाख टन प्याज का निर्यात किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए एनसीसीएफ और नेफेड जैसी संस्थाओं के माध्यम से मुख्य रूप से महाराष्ट्र से 4.68 लाख टन प्याज खरीदा है। वर्मा ने कहा, ''पिछले साल (2023) की तुलना में, चालू वर्ष में प्याज किसानों द्वारा मूल्य प्राप्ति की दर बहुत अधिक रही है। अप्रैल से जुलाई, 2024 के बीच महाराष्ट्र में प्याज की औसत मासिक मंडी मॉडल कीमतें 1,230 रुपये से 2,578 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थीं, जबकि पिछले साल इसी अवधि के लिए यह 693 रुपये से 1,205 रुपये प्रति क्विंटल थी।''

भारत प्याज का शुद्ध निर्यातक देश

चालू वर्ष में बफर के लिए प्याज का औसत खरीद मूल्य 2,833 रुपये प्रति क्विंटल था, जो पिछले साल के 1,724 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद मूल्य से 64 प्रतिशत अधिक है। मंत्री ने कहा, ''भारत प्याज का शुद्ध निर्यातक है और निर्यात से आय अर्जित करता है। पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा अर्जित शुद्ध निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 में 3,326.99 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 4,525.91 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 3,513.22 करोड़ रुपये था।''

चमेलीदेवी लॉ कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 9 से

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

चमेलीदेवी इंस्टीटयूट ऑफ लॉ द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है. जो दिनांक 09 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित विद्वान, शोधकर्ता और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लैंगिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श और नवीनतम शोध को प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं की विषय-वस्तु लैंगिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन, नवीनतम शोध और तकनीकी प्रगति होगी। इस पर विश्वप्रसिद्ध विद्वान और विशेषज्ञ विशेष सत्र और पैनल में चर्चा करेंगें। साथ ही प्रतिभागियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होगा।

भारतीय जनसमूह के बीच ई-कॉमर्स के उपयोग में तेजी आई

टियर 4 यूज़र्स रिपीट शॉपर्स में सबसे ऊपर रहे मीशो की स्मार्ट शॉपर रिपोर्ट

बैंगलुरू। एजेंसी

भारत के एकमात्र टू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, मीशो ने अपनी स्मार्ट शॉपर रिपोर्ट का पहला संस्करण पेश किया है। इसमें 2024 की पहली छमाही में देश के गतिशील शॉपिंग ट्रेंड्स का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में उन ग्राहकों की बदलती आदतों एवं रुचियों के बारे में जानने की कोशिश की गई है, जो वर्तमान में ऑनलाईन शॉपिंग करने वाली आबादी में 80 प्रतिशत हैं।

मीशो ने पिछले 9 सालों में देश में लाखों लोगों के लिए ई-कॉमर्स को आसान बना दिया है। टियर 2 एवं अन्य शहरों से अपने 15 करोड़ वार्षिक विनिमय करने वाले ग्राहकों में से 80 प्रतिशत के साथ मीशो ई-कॉमर्स के नए यूज़र्स

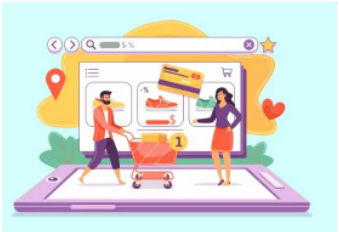

को ऑनलाईन लाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। यह प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स में सबसे विशाल उपभोक्ता आधारों में से एक को सेवाएं देता है। मीशो की सेवाएं भिलाई, इंफाल, जलंधर, झुंझनू, और नेल्लोर जैसे स्थानों के लोगों को प्राप्त होती हैं।

भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले शॉपिंग ऐप्स में से एक के रूप में मीशो की यह स्मार्ट शॉपर रिपोर्ट यूज़र्स की विभिन्न पसंदों की गहरी जानकारी प्रदान करती है, और भारत में विस्तृत ग्राहकों की शॉपिंग की आदतों के रूझान पेश करती है। यह गहन जानकारी प्रदान करके मीशो न केवल उपभोक्ताओं की पसंद की मौजूदा डायनामिक्स पर रोशनी डाल रहा है, बल्कि यह देश में विस्तृत उपभोग का एक भरोसेमंद संकेतक भी है। नीचे बताया गया है कि 2023 में विस्तृत उपभोक्ताओं द्वारा किस प्रकार शॉपिंग की गई।

बजट ने मिडिल क्लास के टैक्स का बोझ घटाया

LTCG में बदलाव लोगों की उम्मीद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट का जोरदार बचाव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ने मध्यम वर्ग के टैक्स बोझ को कम किया है और संपत्ति लेनदेन पर पूंजीगत लाभ कर प्रावधान में ढील देना सरकार द्वारा आम आदमी की उम्मीदों को स्वीकार करने का प्रतिबिंब है। भाषा की खबर के मुताबिक, लोकसभा में वित्त विधेयक (सं. 2), 2024 पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हो गया है। बजट दरों में बढ़ोतरी किए बिना टैक्स व्यवस्था को सरल बनाता है।

जनधन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, वित्त मंत्री ने लोकसभा में दी ये जानकारी

संसद जीएसटी दरों को तय करने का प्लेटफॉर्म नहीं

खबर के मुताबिक, विपक्षी दलों द्वारा अपने सहयोगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी की मांग का इस्तेमाल सरकार पर हमला करने के लिए करने पर, सीतारमण ने कहा कि 2017 में एक समान जीएसटी के अस्तित्व में आने से पहले राज्य प्रीमियम पर टैक्स लगाते थे। उन्होंने कहा कि संसद जीएसटी दरों को तय करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और इसे एक परिषद में जाना होगा, जिसमें राज्यों का दो-तिहाई प्रतिनिधित्व हो। उत्तर के बाद निचले सदन ने 45 संशोधनों सहित विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्य संशोधन अचल संपत्ति लेनदेन पर पूंजीगत लाभ कर लगाने से संबंधित था।

इंडेक्सेशन लाभ बहाल हुआ

आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन द्वारा चिकित्सा और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी वापस लेने की मांग करने वाले संशोधन को नहीं लिए जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। एलटीसीजी टैक्स से संबंधित वित्त विधेयक में संशोधन ने 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ को बहाल कर दिया। अब, 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या एचयूएफ नई योजना के तहत इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की दर से एलटीसीजी टैक्स का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं या इंडेक्सेशन लाभ का दावा कर 20 प्रतिशत कर का भुगतान कर सकते हैं।

नई संपत्ति खरीद के मामले में रोलओवर का लाभ बरकरार

सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को इंडेक्सेशन लाभ के बिना 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था। इस पर खास तौर पर मध्यम वर्ग की ओर से आलोचना की गई थी, जिन्हें लगा कि एलटीसीजी टैक्स देयता में वृद्धि की गई है। हालांकि, अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि काल्पनिक गणनाओं में भी कर भार में कोई वृद्धि नहीं हुई है और नई संपत्ति खरीद के मामले में रोलओवर का लाभ बरकरार रखा गया है। एलटीसीजी टैक्स रेट में बदलाव राजस्व पैदा करने वाली कवायद या लालच नहीं था, बल्कि समान परिसंपत्ति वर्गों के बीच समानता लाने का प्रयास था। यह बदलाव संपत्ति धारक को एक उचित विकल्प और चुनाव देता है। उन्होंने कहा कि चिंताओं को दूर करने के लिए, 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए अब इंडेक्सेशन लाभ का विकल्प वापस लाया गया है।

जनधन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि जन धन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। बैंक द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता है जो अपने खाते में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं। बैंक खातों में ग्राहकों की ओर से न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण 8,500 करोड़ रुपये का जुर्माना सरकारी बैंकों द्वारा बीते 5 वर्षों में वसूले जाने के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही। ऐसे में अगर आपका बैंक जनधन या बेसिक सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नहीं मेनटेन करने पर चार्ज लेता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक की शिकायत आप बैंकिंग लोकपाल के पास भी कर सकते हैं।

लोकसभा में दिया गया लिखित जवाब

सीतारमण ने कहा कि सदन के सदस्यों की ओर से बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर राशि काटे जाने का सवाल उठाया गया है। यह नियम पीएम जन धन खातों और बेसिक सेविंग्स अकाउंट पर लागू नहीं होता है। ये केवल उन खातों पर लागू होता है, जिसमें ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाते में एक सीमा तक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। वित्त मंत्री की ओर से यह जवाब लिखित में लोकसभा में दिया गया।

इन बैंकों ने वसूला भारी जुर्माना

बता दें, जिन सरकारी बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण जुर्माना वसूला गया है उनमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा को बताया था कि न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 24 में 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। यह राशि पिछले साल वसूली गई रकम से 25 प्रतिशत अधिक थी।

वित्त वर्ष 2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 633 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 386 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक द्वारा 369 करोड़ रुपये का जुर्माना न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए वसूला गया है।

टाटा पंच सबसे तेजी से 4 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पर करने वाली एसयूवी बनी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एसयूवी बनाने वाली, भारत की अग्रणी कंपनी टाटा मोटर्स ने यह घोषणा की है कि टाटा पंच ने केवल 34 महीनों में सबसे तेजी से 4 लाख यूनिट्स की बिक्री कर शानदार उपलब्धि हासिल की है। टाटा पंच अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई थी और भारत में इसे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में पेश किया गया था।

अपने ऊँचे कद, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और ड्राइविंग की दमदार पोजीशन के साथ पंच एक आकर्षक और बोल्ड एसयूवी है, जो ड्राइविंग का बेहतरीन अनुभव देती है। यह भारत के विभिन्न इलाकों में आसानी से चलती है। इसका प्रदर्शन करते हुए, टाटा पंच उन पहली फ्रंट-व्हील ड्राइव एसयूवी में से एक के तौर पर उभरी है, जिन्होंने संडकफु में उस ऊँचाई पर जीत दर्ज की, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। खड़ी ढलानों पर अपना रास्ता बनाते हुए, इसने दुनिया को एसयूवी की क्षमता दिखाई है और अपने ही वजन के सामने हर मुश्किल को हराया है।

अपने लॉन्च के पहले ही, पंच को जीएनसीएपी की प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग मिल गई थी। उस समय उसे वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिये जो अंक मिले, वह किसी भी दूसरे वाहन से ज्यादा थे। अगस्त 2022 में पंच ने उद्योग में एक नया मापदण्ड स्थापित किया। सिर्फ 10 महीने की अवधि में वह 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा छूने वाली पहली एसयूवी बन गई। तब से, अगली 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का सफर 9 महीनों में तय हो गया और फिर अगले 7 महीनों में कुल 3 लाख यूनिट्स की बिक्री हो चुकी थी।

16 अगस्त को सिंह राशि में होगा सूर्य देव का गोचर

कर्क-वृश्चिक सहित इन 4 राशियों का खुलेगा सोया हुआ भाग्य

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

सूर्य देव के गोचर पर संक्रांति मनाई जाती है। 16 अगस्त को रवि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 16 अगस्त को सिंह संक्रांति है। इस राशि में भास्कर एक महीने तक रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन ने चार राशि वालों को लाभ होगा। कारोबार और रोजगार में सफलता मिलेगी।

सूर्य गोचर अगस्त 2024

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य देव का 16 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा। भानु शाम 07.53 मिनट पर सिंह राशि में आएंगे। 30 अगस्त को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और 13 सितंबर को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। वहीं, 16 सितंबर से कन्या राशि में गोचर करेंगे।

मिथुन राशि

सूर्य देव मिथुन राशि में कृपा बरसाएंगे। इस दौरान प्रयासों में सफलता मिलेगी। विदेश में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। पार्टनर के साथ शानदार समय का आनंद लेंगे और खुशियां मनाएंगे।

कर्क राशि

सूर्य देव कर्क राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसाएंगे। व्यापार में विशेष लाभ होगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। नौकरी में प्रगति देखने को मिलेगी। जिन जातकों का खुद का बिजनेस हैं उन्हें इस दौरान लाभ प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग बनाने में सफल रहेंगे।

सिंह राशि

सूर्य के गोचर से सिंह राशि के जातक करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस में नई डील मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा।

वृश्चिक राशि

सूर्य देव के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। व्यापार में पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इस दौरान सोच-समझकर धन खर्च करेंगे।

रक्षाबंधन पर भाई को लगाएं केसर का तिलक, चमकने लगेगा भाग्य

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन को समर्पित होता है। साल भर इस त्योहार का इंतजार किया जाता है, क्योंकि इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसके मंगल भविष्य की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी अपनी बहनों को रक्षा करने का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त, सोमवार को मनाया जाने वाला है। इस दिन राखी बांधने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 32 मिनट से लेकर रात 09 बजकर 08 मिनट तक रहने वाला है। इस दौरान बहनें अपने भाईयों को राखी बांध सकती हैं। राखी बांधते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, तो भाई के लिए आने वाला समय काफी लाभकारी होता है।

केसर का तिलक लगाएं

रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले तिलक करती हैं। यह तिलक रोली से किया जाता है। लेकिन यदि आप केसर से भाई का तिलक करती हैं, तो उसके जीवन में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा होती है।

भाई को नारियल दें

कहा जाता है कि राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को एक नारियल जरूर दें। नारियल श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल देने से जीवन में संपन्नता बनी रहती है। साथ ही इसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। ऐसे में मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है।

राखी बांधते समय बहनें बोले ये मंत्र

बहनें जब भाई के हाथ पर राखी बांध रही हो, तो उन्हें ये मंत्र बोलना चाहिए।

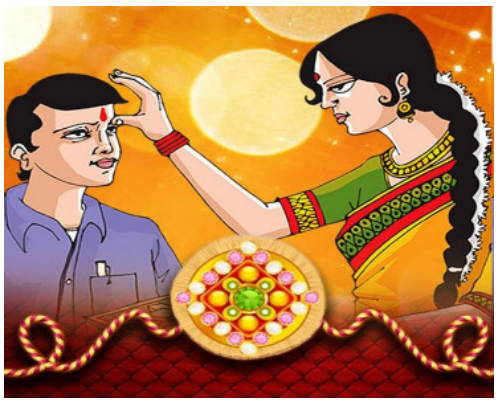

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः
तेन त्वाम् अभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल?

भाई को दें रुमाल

रक्षाबंधन के दिन यदि बहनें अपने छोटे भाईयों को राखी बांध रही है, तो उन्हें वस्त्र देने का विधान है। लेकिन यदि आप वस्त्र नहीं दे पा रही हैं, तो आप उसे रुमाल भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भाई के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। रुमाल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है।

बहनें भाई को जरूर दें कुछ रुपये

रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को नारियल के साथ गुडलक के तौर पर कुछ रुपये भी जरूर दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से भाई के जीवन में गुड लक बढ़ता है।

आखिर क्यों शिवलिंग से पहलें अशोक सुंदरी को किया जाता हैं जल अर्पित, जानिए

पंडित कपिल पाराशर
ज्योतिष आचार्य
वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से पूर्व उनकी पुत्री अशोक सुंदरी की पूजा की जाती हैं। अशोक सुंदरी को सौंदर्य की देवी माना जाता हैं। अशोक सुंदरी कि पूजा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती हैं। इसीलिए अशोक सुंदरी की पूजा-आराधना शिवलिंग में ही समाहित होती हैं। शिवलिंग में भगवान शिव ने अशोक सुंदरी को स्थान दिया था और तभी से शिवलिंग की पूजा के समय ही अशोक सुंदरी की पूजा का विधान हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो शिवलिंग के आगे एक नलिका बनी होती है जिससे शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बाहर जाता हैं। उसी स्थान पर अशोक सुंदरी का वास माना गया हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद लोटे में थोड़ा सा जल बचाकर आखिर में अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख-समृद्धि और संपन्नता बनी रहती हैं।

घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए शनिदेव की मूर्ति, जानिए क्या है कारण

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

हर घर के मंदिर में अलग-अलग देवी-देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर के मंदिर में कुछ देवी-देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इन मूर्तियों के रखे होने से नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आइए, जानते हैं कि घर के मंदिर में किन देवी-देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखना चाहिए।

शनिदेव की मूर्ति

हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव की पूजा की जाती है, लेकिन घर के मंदिर में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखना वर्जित होता है। उन्हें एक उग्र देव माना जाता है। इसलिए शनिदेव की पूजा घर की बजाय किसी मंदिर में जाकर करना शुभ मना होता है।

मां काली की मूर्ति

शनिदेव की तरह ही घर के मंदिर में मां काली की मूर्ति और तस्वीर रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इन्हें भी उग्र देवताओं में शामिल किया जाता है। इनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। मां काली की पूजा के नियम भी बहुत कठिन हैं और घर पर ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है।

नटराज की मूर्ति

कई लोगों के घर में नटराज की मूर्ति रखी होती है, लेकिन नटराज असल में भगवान शिव का रौद्र रूप माने जाते हैं। ऐसे में घर के मंदिर में नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह बनी रहती है।

भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति

देवी-देवताओं की मूर्तियां भी विभिन्न मुद्राओं में पाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि घर में हमेशा भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति ही लानी चाहिए। मंदिर में देवी-देवताओं की मूर्तियां खड़ी या किसी अन्य स्थिति में रखना शुभ नहीं माना जाता है।

भारत में खपत से ज्यादा खाद्यान्न की पैदावार

दुनिया का पेट भरने की कर रहे तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत एक खाद्य अधिशेष (खपत से ज्यादा खाद्यान्न की पैदावार) देश बन गया है। अब भारत दुनिया का पेट भरने और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। खाद्य अधिशेष से मतलब देश में उपभोग से ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध होने से है। भारत में 65 वर्षों के बाद आयोजित किए जा रहे कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का आम बजट 2024-25 टिकाऊ खेती पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, 'भारत अब एक खाद्य अधिशेष देश है। यह दुनिया में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा, भारत खाद्यान्न, फल, सब्जी, कपास, चीनी और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है।'

भारत ने बदली अपनी तस्वीर

मोदी ने कहा कि पिछली बार जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब उसे आजादी मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह दौर देश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण दौर था। प्रधानमंत्री ने कहा, "एक दौर था, जब भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का सबब थी। अब, भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है।" कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के 70 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स' की ओर से यह त्रिवार्षिक सम्मेलन दो से सात अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।

फसलों की 1,900 नयी प्रजातियां प्रदान की

इस वर्ष के सम्मेलन का विषय "सतत कृषि-खाद्य प्रणालियों की ओर" है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील फसलों की 1,900 नयी प्रजातियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। मोदी ने कहा कि देश पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेगा और कृषि अनुसंधान एवं नीति में देश की प्रगति को रेखांकित करेगा। इसका मकसद युवा शोधकर्ताओं और अग्रणी पेशेवरों को वैश्विक समकक्षों के साथ अपने काम और नेटवर्क को पेश करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

लोग जमकर खरीद रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल

जुलाई में 55% बढ़ गई सेल्स, ईवी टू-व्हीलर का जबरदस्त क्रेज

नई दिल्ली। एजेंसी

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 55.2 प्रतिशत बढ़कर 1,79,038 इकाई रही। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक-दोपहिया वाहनों की बिक्री में 96 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि से कुल बिक्री बढ़ी है। वाहन डीलरों का निकाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के बिक्री आंकड़ों के अनुसार बीते साल जुलाई में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1,16,221 इकाई थी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 95.94 प्रतिशत बढ़कर 1,07,016 इकाई रही। जुलाई 2023 में यह संख्या 54,616 इकाई थी।

कमर्शियल व्हीकल्स की सेल दोगुनी बढ़ी

वहीं, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री 18.18 प्रतिशत बढ़कर 63,667 इकाई रही। पिछले साल इसी महीने में यह 58,873 इकाई थी। फाडा के आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य माह में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री दो गुना से अधिक होकर 816 इकाई रही। बीते वर्ष जुलाई में 364 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री की गयी थी। हालांकि, जुलाई में यात्री वाहनों की बिक्री 2.92 प्रतिशत घटकर 7,541 इकाई रही। जुलाई 2023 में यह 7,768 इकाई थी।

टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर ईवी का मार्केट शेयर बढ़ा

फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, "दो पीहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है। सालाना आधार पर जुलाई में वृद्धि दर क्रमशः 95.94 प्रतिशत और 18.18 प्रतिशत रही। वहीं, बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 57.6 प्रतिशत रही। इससे यह साफ है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता और उसकी मांग बढ़ रही है।" सिंघानिया ने कहा कि यात्री वाहन सेगमेंट में सालाना आधार पर 2.92 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई है, लेकिन बाजार हिस्सेदारी 2.4 प्रतिशत बनी हुई है। वहीं वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट में सालाना आधार पर 124.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसकी वर्तमान में (जुलाई में) बाजार हिस्सेदारी 1.02 प्रतिशत है।

फोनपे ने प्री-अप्रूव्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया

नई दिल्ली। एजेंसी

फोनपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर 'प्री-अप्रूव्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस' फीचर लॉन्च करने की घोषणा की। इस फीचर का उद्देश्य पॉलिसी खरीद के समय इनकम प्रूफ की जरुरत को खत्म करके लाखों भारतीयों के लिए इंश्योरेंस कवरेज को अधिक आसान और किफायती बनाना है। इस लॉन्च के साथ, फोनपे इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने में उसे आसान बनाकर भारत में वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक नया अध्याय शुरू कर रहा है, जिससे लोगों को परेशानी मुक्त आय को वेरिफिकेशन किए बिना जल्द और आसानी से लाइफ इंश्योरेंस लेने की सुविधा मिलेगी।

कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर इस सुविधा को शुरू करने के लिए प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। यह पार्टनरशिप इंश्योरेंस कंपनियों को अब ज्यादा यूजर को विशेष रूप से 30 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने में मदद करेगी, जो पहले इनकम प्रूफ के अभाव में टर्म इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा पाते थे। लाखों फोनपे यूजर, जिनमें मर्चेंट, स्व-नियोजित व्यक्ति, गिग कर्मचारी और बिना औपचारिक इनकम प्रूफ वाले अन्य लोग शामिल हैं, अब फोनपे प्लेटफॉर्म पर आसानी से टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में, कंपनी इस ऑफर को व्यापक स्तर पर बढ़ाने तथा इसकी पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि इस वर्ष के अंत तक इसे 50 मिलियन यूजर तक पहुंचाया जा सके। लॉन्च पर बात करते हुए, फोनपे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के सीईओ विशाल गुप्ता जी का कहना है कि, 'हम अपने प्लेटफॉर्म पर 'प्री-अप्रूव्ड सम एश्योर्ड (PASA)' फीचर के लॉन्च की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। इस लॉन्च का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों वाले भारतीयों के लिए इस प्रोडक्ट को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर इससे वंचित ग्राहकों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस के दायरे में लाना है।

टमाटर ने महंगी कर दी शाकाहारी थाली, 11 प्रतिशत

बढ़ी कीमत, जानिए मांसाहारी थाली के दाम

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मासिक आधार पर टमाटर की कीमतों में उछाल आने से जुलाई के महीने में शाकाहारी थाली 11 प्रतिशत तक महंगी हो गई। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की मासिक 'रोटी चावल दर' रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2024 की तुलना में जुलाई में मांसाहारी थाली भी छह प्रतिशत महंगी हो गई है। रिपोर्ट कहती है कि रोटी, सब्जियां (प्याज, टमाटर और आलू), चावल, दाल, दही और सलाद वाली शाकाहारी थाली की कीमत जुलाई 2024 में 32.6 रुपये प्रति प्लेट थी, जबकि जून 2024 में इसकी दर 29.4 रुपये प्रति प्लेट थी।

61.4 रुपये प्रति प्लेट हो गई मांसाहारी थाली

रिपोर्ट के मुताबिक, "जून की तुलना में जुलाई महीने में शाकाहारी थाली की कीमतों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण टमाटर की कीमतों में उछाल आना था। इसका शाकाहारी थाली की कीमत बढ़ोतरी में सात प्रतिशत योगदान रहा।" मांसाहारी थाली की कीमत भी जुलाई के महीने में छह प्रतिशत बढ़कर 61.4 रुपये प्रति प्लेट हो गई, जबकि जून में इसकी कीमत 58 रुपये प्रति प्लेट थी। मांसाहारी थाली में अमूमन शाकाहारी थाली वाली सामग्री ही होती है, लेकिन उसमें दाल की जगह चिकन होता है।

सालाना आधार पर घटे हैं दाम

हालांकि, सालाना आधार पर शाकाहारी थाली के दाम जुलाई में चार प्रतिशत घट गए। इसका मुख्य कारण टमाटर की कीमतों का उच्च आधार प्रभाव था। जुलाई 2023 में शाकाहारी थाली का दाम 34.1 रुपये प्रति प्लेट था। जुलाई 2024 में टमाटर की कीमत 66 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो जुलाई 2023 के 110 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है। पिछले साल जुलाई में टमाटर की ऊंची कीमतों के लिए उत्तरी राज्यों में अचानक आई बाढ़ और कर्नाटक में कीटों का प्रकोप जिम्मेदार था। हालांकि, जुलाई 2024 में टमाटर की कीमत जून 2024 के 42 रुपये प्रति किलोग्राम से काफी अधिक रही। अधिक तापमान से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में टमाटर की फसल पर असर पड़ा है। हालांकि, जुलाई 2023 के मुकाबले प्याज की कीमतों में 65 प्रतिशत और आलू की कीमतों में 55 प्रतिशत की वृद्धि होने से शाकाहारी थाली की लागत में कुल कमी सिर्फ चार प्रतिशत तक सीमित रह गई। मांसाहारी थाली के मामले में लागत एक साल पहले की तुलना में नौ प्रतिशत घटकर 61.4 रुपये प्रति थाली रह गई। मुख्य रूप से ब्रॉयलर (मुर्गे) की कीमतों में 11 प्रतिशत की गिरावट आने से ऐसा हुआ।

एसबीआई म्यूचुअल फंड व्दारा निवेशकों के लिए

एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड योजना

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नवाचार केप्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप निवेशकों के लिए एक नया फंडएसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड का आरंभ किया है । यहफंड मुख्यतः ओपन-एंडेड श्रेणी में है । नई रणनीतियों औरअवधारणाओं को भुनाने की चाहत रखने वाली कंपनियों केइक्विटी और इक्विटी-संबंधित विकल्पोंमें निवेश करके निवेशकोंको दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना, यह इस फंडका मुख्य निवेश उद्देश्य है । हालाँकि, इस बात का कोईआश्वासन नहीं दिया जा सकता कि, योजना के निवेश उद्देश्य पूरेहोंगे । इस फंड के लिए निफ्टी 500 टीआरआई बेंचमार्क इंडेक्स होगा ।

नए फंड के लॉन्च पर बोलते हुए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंटलिमिटेड के प्रबंध निदेशक

और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. शमशेर सिंह (Shamsher Singh) ने कहा, 'आज हमारा देशदुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है औरविकसित भारत का केंद्र बिंदु इनोवेशन बन गया है । स्टार्ट अपइंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और इंडिया स्टैक जैसी पहलों केमाध्यम से स्कूल से लेकर उद्योग तक नवाचार की संस्कृति औरमजबूत बनाना यह सरकार का लक्ष्य है । एक बड़े उपभोक्ताबाजार के साथ-साथ एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे केसाथ एक संपन्न स्टार्टअप और निवेश अर्थव्यवस्था वर्तमान मेंहमारे देश को नवाचार क्षितिज पर एक नेता के रूप में उभरने केलिए कई अनुकूल कारक प्रदान कर रही है । प्रतिस्पर्धा में आगेरहने के लिए लगातार नवाचार कर रहे और ग्राहकों को प्रदानकिए जाने वाले तत्वों में मूल्य जोड़ने के लिए अलग तरीके से कामकर रहे कंपनियों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों के लिएएसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक शानदार अवसर है।'

सैमसंग ने 'इंडिया चीयर्स फॉर नीरज' कैम्पेन की घोषणा की

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

सैमसंग ने अपने 'इंडिया चीयर्स फॉर नीरज' कैम्पेन के जरिए प्रशंसकों से आगे आने और नीरज चोपड़ा को अपनी शुभकामनाएं भेजने का अनुरोध किया है। इस कैम्पेन के साथ, सैमसंग इंडिया नीरज को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपनी सीमाओं से आगे जाने के लिए सपोर्ट करना चाहता है। उपभोक्ताओं के उत्साह को दिशा देने और राष्ट्र के सामूहिक उत्साह को बढ़ाने के लिए, सैमसंग इंडिया ने नीरज चोपड़ा के लिए सपोर्ट जुटाने के लिए एक फिल्म का अनावरण किया है। इस फिल्म में दिग्गज एथलीट की मजबूती और दृढ़ संकल्प शक्ति को दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि नीरज कई चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। यह फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि सैमसंग का हाल ही में लॉन्च किया गया गैलेक्सी Z फोल्ड6 स्मार्टफोन उनकी इस यात्रा में कैसे मदद करता है। गैलेक्सी Z फोल्ड6 अपनी शक्तिशाली गैलेक्सी एआई टेक्नोलॉजी के साथ सीमाओं से आगे जाकर उपभोक्ताओं को बेजोड़ अनुभव प्रदान करता है। गैलेक्सी एआई से पावर्ड गैलेक्सी Z फोल्ड6 इंटरप्रेटर और नोट असिस्ट जैसे एआई फीचर्स के साथ आता है, जिसकी मदद से यूजर्स अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं, यह उनकी उत्पादकता बढ़ाता है और उनके काम करने और जीने के तरीके को बदलने की सुविधा देता है।

कोटक-गोकी स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्टवॉच हुई लॉन्च

स्मार्टवॉच रूपे ऑन-द-गो से पावर्ड, पिन के बगैर ही 5000 रूपये तक के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोटक महिन्द्रा बैंक लि. ('केएमबीएल' / 'कोटक') ने गोकी के साथ साझेदारी कर कोटक- गोकी स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्टवॉच लॉन्च की है। यह साझेदारी ग्राहकों के भुगतान करने का तरीका बदल देगी। इस अभिनव और वियरेबल डिवाइस की कीमत 3499 रूपये है। इसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और सेहत पर नजर रखने के फीचर्स दिए गए हैं। यह स्मार्टवॉच रूपे ऑन-द-गो से पावर्ड है और इससे 5000 रूपये तक का ट्रांजैक्शन पिन की जरूरत के बगैर आसानी से हो सकता है। उत्पाद को लॉन्च करते हुए, कोटक महिन्द्रा बैंक में रिटेल लाएबिलिटीज प्रोडक्ट के

हेड और चीफ मार्केटिंग ऑफीसर रोहित भसीन ने कहा, "आजकल हम डिजिटल तरीके से पैसे का लेन-देन बहुत करते हैं। छोटे-मोटे खर्चों के लिए भी हमें बार-बार पैसे निकालने या कार्ड स्वाइप करने या स्मार्टफोन से पेमेंट करने की जरूरत होती है। लेकिन अब कोटक-गोकी स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्टवॉच इन सब परेशानियों को दूर कर देती है। इस स्मार्टवॉच से चलते-फिरते सुरक्षित एवं बिना किसी परेशानी के बैंकिंग हो सकती है।"

कोटक- गोकी स्मार्ट वाइटल प्लस के द्वारा यूजर्स ब्लड प्रेशर, शरीर का तापमान और एपीओ2 लेवल्स सीधे अपनी कलाई पर देख सकते हैं। इसके अलावा, यूजर के लिये अनुकूल इंटरफेस से आसान भुगतान सुनिश्चित होता है। ग्राहक बिना किसी परेशानी के अपने कोटक अकाउंट्स के साथ साइन इन कर सकते हैं और इस उपकरण पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। इसमें पारंपरिक कॉन्टैक्टलेस काड्र्स और मोबाइल डिवाइसेस जैसी ही सुरक्षा मिलती है।

हीरो मोटोकॉर्प और एफआईएच ने वैश्विक साझेदारी की

हॉकी के विकास के लिए नई साझेदारी के साथ सहयोग को और मजबूत किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ पांच साल के लिए नई साझेदारी की घोषणा की है। हॉकी के विकास के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण समझौते के साथ हीरो मोटोकॉर्प, एफआईएच का ग्लोबल लीडरशिप पार्टनर बन गया है। कंपनी ने पिछले 15 सालों से वैश्विक हॉकी के साथ अपने मजबूत और लंबे समय के जुड़ाव की पुष्टि की है।

इस रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, हॉकी के वैश्विक विकास को बढ़ावा देना और दुनिया भर में हॉकी प्रेमियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना है।

डॉ. पवन मुंजाल और तैय्यब इकराम ने इस आपसी पर सहयोग पर चर्चा करने के लिए वर्तमान में चल रहे पेरिस ओलंपिक के दौरान मुलाकात की। इन अनुबंध के बारे में हीरो मोटोकॉर्प के एक?जीक?यूटिव चेयरमैन डॉ. पवन मुंजाल ने कहा इस समय दुनिया ओलंपिक खेलों के लिए इकट्ठा

FIH | Hero
Global Leadership Partner

हुई है, ऐसे में मुझे अगले पांच सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के साथ अपनी साझेदारी का नवीकरण करने की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। यह सहयोग सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल अनुबंधों में से एक है। भारत में, हॉकी राष्ट्रीय गौरव और विरासत का प्रतीक है।

धार में अल्ट्राटेक लाइमस्टोन माइन को भारतीय खान ब्यूरो और खान मंत्रालय से मिली 5 स्टार रेटिंग

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय खान ब्यूरो ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की 12 लाइमस्टोन माइन को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है। यह अवार्ड कोयला व खनिज मंत्री द्वारा दिल्ली में 7 अगस्त 2024 को दिया गया। जिन 12 खदानों को 5 स्टार रेटिंग मिली है, उनमें सीतापुरी लाइमस्टोन माइन भी शामिल है। जो मध्य प्रदेश के धार जिले में अल्ट्राटेक की एकीकृत इकाई, धार सीमेंट वर्क्स का हिस्सा है। कार्यक्रम में माननीय श्री जी. किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्री ने भारत की सबसे बड़ी सीमेंट और रेडी-मिक्स कंक्रीट कंपनी अल्ट्राटेक को सम्मानित किया। यह सम्मान भारत के खनन क्षेत्र में योगदान देने और खनन के सभी पहलुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। सम्मान समारोह में माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित थे। खनन में उत्कृष्टता लाने के लिए अल्ट्राटेक के प्रयास भारतीय खान ब्यूरो के स्थायी खनन (सस्टेनेबल माइनिंग), कुशल संचालन और प्रौद्योगिकी-संचालित खनिज प्रसंस्करण के लक्ष्यों के अनुरूप हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अल्ट्राटेक को खानों की सभी श्रेणियों (लाइमस्टोन, लौह अयस्क, बॉक्साइट, सीसा जस्ता, मैंगनीज) में सबसे अधिक खदानों के लिए 5-स्टार रेटिंग दिए जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। खान मंत्रालय द्वारा तैयार की गई स्टार रेटिंग सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और स्थाई विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने पर आधारित है। रेटिंग योजना में सबसे उच्च 5-स्टार रेटिंग उन खदानों को दी जाती है जिन्होंने वैज्ञानिक और कुशल खनन, अनुमोदित उत्पादन का अनुपालन, जीरो वेस्ट, पर्यावरण संरक्षण, प्रगतिशील और अंतिम खदान बंद करने के लिए उठाए गए कदम, ग्रीन एनर्जी सोर्सिंग, भूमि, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना, समुदायों के जुड़ाव और कल्याण कार्यक्रम, स्थानीय पुनर्वास और अन्य सामाजिक प्रभावों जैसे मापदंडों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।